

सम्पादकीय

सीमित हुआ आधार उपयोग

आधार नंबर पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के बाद इस पर जारी विवाद बंद हो जाना चाहिए। न्यायालय ने साफ विभाजन रेखा खींच दिया है कि कहां आधार नंबर देना जरुरी है और कहां नहीं। जाहिर है, इससे संविधित भ्रम साफ हो गया है। आयकर रिटर्न भरने, पैन कार्ड बनवाने एवं सरकारी लाभकारी योजनाओं और सक्षिप्ति प्राप्त करने के अलावा कहीं भी आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। यही नहीं बैंकों, मोबाइल कंपनियों या ऐसे सेवा प्रदाताओं द्वारा आधार नंबर मांगना अब अवैध होगा। न्यायालय द्वारा आधार कानून की धारा 57 को रद्द कर देने के साथ ही निजी कंपनियों के आधार नंबर मांगने के अधिकार समाप्त हो गए हैं। सच है कि आधार नंबर का जैसा अतिवादी प्रयोग होने लगा था, उससे लोगों को परेशानी हो रही थी और खीझ भी पैदा होती थी। अगर बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है तो आप उसे जरूरी सेवाओं से वंचित कर देंगे यह कहां का न्याय है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने जनिहत को ध्यान में रखते हुए उचित फैसला दिया है। किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि इसने याचिकाकर्ताओं की यह दलील भी मान ली है कि आधार कार्ड निजता का अतिक्रमण है और यह संविधान में मिले मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। पीठ द्वारा बहुमत से इसकी संवैधानिकता की स्वीकृति सरकार के लिए बहुत बड़ी राहत है। इस फैसले से यह आशंका भी समाप्त हो गई है कि इसमें दी गई जानकारियां सुरक्षित नहीं हैं। न्यायालय ने यह कहकर सरकार का पक्ष मजबूत भी किया है कि आधार आम लोगों के हित के लिए काम करता है और इससे समाज में हाशिये पर बैठे लोगों को फायदा होगा। साफ है कि शीर्ष अदालत संवैधानिकता के मामले में सरकार के साथ है तो सुरक्षा मामले में यूरेआईडीआई के प्रमाणों को सही मानता है। लेकिन सरकार पर यह बंधन लग गया है कि वह बिना न्यायालय की इजाजत के बायांमीट्रिक डेटा को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर किसी और एजेंसी से शेयर नहीं कर सकती। कई बार इससे सरकार को परेशानी आएगी व्यांकि किसी पर कोई मामला दर्ज हो तो जांच एजेंसियों को उसका बयोमेट्रिक डेटा चाहिए होगा। न्यायालय का आदेश मिलने में देर होने पर जांच में बाधा आ सकती है। बावजूद इसके डेटा सुरक्षित रखने के पूर्वापाय के तौर पर देखा जाना चाहिए।

ਨਹੀਂ ਲਗ ਸਕੀ ਦਾਗੀ ਨੇਤਾਓਂ ਪਰ ਰੋਕ

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
आपाराधिक मामलों के कारण
किसी के चुनाव लड़ने या न
लड़ने पर फैसला देने से इनकारा
करना वास्तव में हमारे संविधान
में शासन के तीनों अंगों के
बीच खींची गई विभाजन
रेखा के अनुरूप है।
न्यायालय का यह कहना
बिल्कुल सही है कि इस
विषय का निपटारा संसद
करे यानी जिन लोगों पर
आपाराधिक मामले हैं,
उनको चुनाव लड़ने से
रोकना है तो इस पर
कानून बनाने का अधिकार
संसद को है। हमारे
संविधान में भी कानून
बनाने, संविधान में संशोधन



हैं। राजनीति में सक्रिय लोगों पर भी आक्रामक विरोध और अन्य अनेक कारणों से ऐसे मामले दायर हो जाते हैं, जिनमें 5 वर्ष से ज्यादा की सजा का प्रावधान है। न्यायालय के सामने जो याचिकाएं थीं उनमें यही अपील की गई थी कि जिन पर 5 वर्ष या इससे ज्यादा सजा मिलने कहा गया कि यह विषय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। सर्वोच्च न्यायालय पहले ही यह फैसला दे चुका है कि जिसे भी दो वर्ष या उससे अधिक की सजा मिल गई हो, उसकी संसद और राज्य विधायिकाओं की सदस्यता खत्म हो जाएगी और सजा समाप्त और अपराधियों को बाहर करना का विचार निःसंदेह प्रशंसनीय है, पर इस तरह से तो जौ कर और धून ज्यादा पिस जाएंगे। राजनीतिक दलों को ही यह विचार करना पड़ेगा कि जिनके वाकई आपराधिक पृष्ठभूमि हैं उनको वे अपने उम्मीदवार बनाएं।

देश के स्वास्थ्य की चिंता सबसे पहले

बीमारी से जूझना इस मुल्क में हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। साधन-संपन्न ही ऐशो—आराम अफोर्ड कर सकते हैं, वो ही बीमारी भी अफोर्ड कर सकते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे 2013–14 के आंकड़ों के हिसाब से इस मुल्क में होने वाली मौतों की करीब एक तिहाई मौतों से पहले कोई मेडिकल सहायता नहीं मिलती यानी वो मौतें बिना किसी चिकित्सकीय सहायता के हो जाती हैं। लाखों के इलाज की कीमत सुनकर गरीब आस बिल्कल छोड़ देता है। आंकड़ों



करने वाली आयुष्मान योजना के शुरूआती परिणाम सकारात्मक और संतोषजनक आए तो अगले लोक सभा चुनाव में यह भाजपा सरकार के लिए बड़ा मुद्दा होगा। पचास करोड़ जनसंख्या का मतलब है कि मुल्क की आबादी का रीब चालीस फीसद हिस्सा योजना से लाभान्वित हो सकता है। यह संख्या बहुत बड़ी है, भाजपा आयुष्मान योजना के राजनीतिक लाभांश न ले जाए, यह स्वाभाविक चिंता भाजपा की हर प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक पार्टी को होनी चाहिए और वह है भी। यह योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना मानी जा सकती है।

योजना को जमीन पर उतारने में होती हैं। निजी क्षेत्र के अस्पतालों का ट्रैक रिकॉर्ड विपन्न तबकों को चिकित्सकीय मदद के मामले में खराब ही नहीं, अमानवीय रहा है। दिल्ली में तमाम निजी अस्पतालों को सरकार ने लगभग मुफ्त में जमीन उपलब्ध कराई थी, इस शर्त पर कि वहां गरीब तबकों का सस्ता इलाज होगा। पर बहुत मुश्किलें पेश आ रही हैं गरीबों के इलाज में। कहना यह कि निजी क्षेत्र के लिए आयुष्मान योजना कमाई का माध्यम नहीं बनी तो पक्का है कि वह इसे बराये नाम भर कागज पर चलाए रखेगा। कोई दोष

मोटे तौर पर योजना कुछ यूं काम करेगी कि इसका लाभ उठाने के पात्र परिवारों के पास कार्ड होगा। उस कार्ड को दिखाकर वह परिवार अपने बीमार सदस्यों का तय सरकारी या निजी अस्पतालों में इलाज करवा सकेंगे। उन्हें कोई भुगतान नहीं करना होगा। भुगतान की जिम्मेदारी सरकार ही होगी। — निजी वित्तीय वेलाएँ रखना। काइ ठास उपलब्धि नहीं मिल पाएगी। जैसा कि संकेत मिल रहे हैं, निजी क्षेत्र की तरफ से आयुष्मान भारत योजना के कई रेटों पर असंतोष जताया जा रहा है। सिजिरियन ऑपरेशन का रेट आयुष्मान योजना में 9000 रुपये रखा गया। यानी कोई निजी अस्पताल सीजिरियन आपरेशन 9000 में करेगा पर

ਲੁਧਿਆਣਾ/ ਪ੍ਰਦੇਸ਼

जनसंख्या विस्फोट पर दुष्कर है रोक लगाना

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक 2050 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश होगा यानी चीन को भी भारत आबादी के मामले में पछाड़ देगा। यदि आबादी की रफ्तार और भी तेज हुई तो 2050 के पहले ही भारत सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन जाएगा। जो आंकड़े बढ़ती आबादी के राज्यवर केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तुत किए गए हैं, उससे यह साबित होता है कि देश के बड़े राज्यों की अपेक्षा छोटे राज्यों ने आबादी की रफ्तार पर काबू पाने में अधिक सफलता पाई है। ये राज्य हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली, आंध्र, हिमाचल, गोवा, पंजाब, ओडिशा और जम्मू-कश्मीर। बढ़ती आबादी के साथ घटते संसाधन और इसी के साथ बढ़ती वेरोजगारी देश में कई आसन्न समस्याओं को जन्म देते दिखाई दे रहे हैं, जो विकास की राह में बहुत बड़े रोड़े साबित हो सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के तमाम परिवार नियोजन की योजनाओं, अभियानों और कार्यक्रमों तथा स्वयंसेवी संगठनों की सशक्त भूमिका के बावजूद भारत में जनसंख्या की समस्या लगातार बढ़ती रही है। मौजूदा भारत की आबादी 1.25 एक सौ पच्चीस करोड़ से अधिक हो गई है। संयुक्त राष्ट्रसंघ के मुताबिक 2025 तक यह चीन की आबादी को भी पीछे छोड़ देगा। इस वक्त भारत की आबादी 1.45 एक अरब पच्चीस करोड़ के करीब होगी।

आबादी बढ़ने की रफ्तार कम जरूर हुई है, लेकिन जन्म दर की अपेक्षा मृत्युदर कम होने के कारण महज 2001 से 2010 के दौरान 18.14 करोड़ की बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले पांच सालों में लगभग औसत जनसंख्या बढ़ने का यही हाल रहा है। यह वृद्धि पिछली जनसंख्या के आंकड़ों की तुलना में 17.64 प्रतिशत अधिक है। अब भी भारत की जनसंख्या 1.4 प्रतिष्ठत वार्षिक दर से बढ़

रही है जो कि चीन के 0.6 से ढाई गुना अधिक है। विषेशज्ञों के मुताबिक पानी, जमीन, खाद्यान्न, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ और अन्य आवश्यक संसाधनों में लगातार कमी आती जा रही है। सबसे बड़ी समस्या इस वक्त पीने वाले पानी और शुद्ध खाद्यान्न की है। देश के अभी हजारों गांवों में जरूरत के अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और पीने लायक पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई है। इससे गांवों से लगातार पलायन हो रहा है और शहरी आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। एक आंकड़े के मुताबिक यदि गांवों से शहरों की ओर होता पलायन नहीं रुका तो 2030 तक शहरों की आबादी बढ़कर 40 फीसद से ज्यादा हो जाएगी। इससे शहरों में जनसंख्या का भार और बढ़ेगा जिससे नई-नई समस्याएं बढ़ेंगी। ऐसे में सवाल उठता है कैसे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य, मकान, कपड़ा, शुद्ध पीने का पानी और खाना, साथ ही अच्छी शिक्षा मुहैया कराई जाए। जाहिर है शहरों में गैरबराबरी बहुत तेजी से बढ़ रही है। गरीब आदमी छोटे परिवार की जगह बड़ा परिवार बनाने को प्राथमिकता देता है। उसके सोच के पीछे शारीरिक श्रम के जरिए परिवार की आमदनी बढ़ाने की होती है। उसे न तो बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य की कोई चिंता रहती है और न तो मूलभूत बेहतर सुविधाओं की। आबादी की जो समस्या है, वह निम्न आय वर्गीय वालों की है, सरकार और एनजीओ को सबसे पहले यहां ध्यान देने की जरूरत है। देश में दूध और खाद्यान्न की कमी कोई नई बात नहीं है। खासकर दालों की अनुपलब्धता लगातार बनी रहती है। हालात यहां तक आ पहुंची है कि पानी, दूध और दलहन को बाजार में उपलब्धता बनाए रखने के लिए बहुराटीय कंपनियों को ठेका दिया जा रहा है, जिससे अरबों रुपये भारत से बाहर जा रहा है। बढ़ती आबादी के कारण प्राकृतिक संसाधन का दोहन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पर्यावरण प्रदूषण की गहराती समस्या का एक बड़ा कारण यह भी है। भारत में बढ़ती आबादी की समस्या इसका स्थिरीकरण न होना है। स्थिरीकरण का मतलब, साल भर में जन्म लेने वाले वालों की संख्या तकरीबन उतनी ही होगी जितने लोगों की मौत होती है। वैज्ञानिक अनुमानों के मुताबिक यदि टीएफआर दर 2020 में 2.1 फीसद आ जाती है तो उसके 35 साल बाद 2055 में आबादी का स्थिरीकरण हो पाएगा। जिसकी सम्भावना बहुत कम है। तमाम कवायदों के बावजूद लोगों में छोटे परिवार रखने के प्रति वैसी ललक नहीं बन पाई है जैसी आबादी के स्थिरीकरण के लिए जरूरी है। सरकार को कुछ ऐसी योजनाएं निकालनी चाहिए, जिससे खेती और बागवानी पर मानव श्रम-शक्ति के कारण उस पर असर न पड़े और लोगों को परिवार नियोजन कराने के बाद परेशानी पैदा न हो।

पाक की भारत से वार्ता की चाहत पर ग्रहण

भारत और पाकिस्तान के बीच मंत्रियों की न्यूयार्क में बाली भेट का रद्द होना वो दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन वो भी ज्यादा बुरा यह हुआ दोनों देशों की तरफ से सरकार को कौन चला रहे हैं? नेता या अफसर? जो तीसरा कारण बताया गया है, भेट के रद्द होने का, वह भी संदेह के घेरे में है। कश्मीर के आतंकवादी आए दिन ऐसे को वह न्यूयार्क की भेट में जमकर उठातीं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज शब्दों की मिलिका हैं। वह कुरैशी की बोलती बंद कर देतीं। कुरैशी उनसे जरूर प्रभावित होते और के नेता पहले भी पाकिस्तानी दूतावास से सतत संपर्क में रहते थे और उनसे प्रधानमंत्री नरसिंह ने भेट के भंग होने पर मोदी के



कारनामे करते रहते हैं, जो वहशीपन से कम नहीं हैं। इसमें शक नहीं कि इन आतंकवादियों को पाकिस्तान की शेरी भी रहती है। हो सकता है कि यह मामला भी पाकिस्तानी फौज के इशारे पर किया गया हो लेकिन उसके ठोस प्रमाण अभी तक सामने नहीं आए हैं। मान लें कि पाक फौज ने ही यह करवाया है, तो भी इसके बहाने भेट को भंग करवाना कोई बुद्धिमानी नहीं है। पाक फौज ऐसे जघन्य कृत्य अक्सर करवाती ही रहती है। यह जो कृत्य था, इसमें नया क्या था? अजूबा क्या था? यह भी हो सकता है कि कश्मीर या पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी संगठनों ने जान-बूझकर इस वक्त यह करतूत की हो ताकि भारत-पाक संवाद के पहले ग्रास में ही मक्खी पड़ जाए। मक्खी तो पड़ गई। यानी हमारी सरकार आतंकवादियों की चाल का मोहरा बन गई। यदि सरकार में दूरवृष्टि और पर्मिट्स तो भी तो उन्हीं पर्मिट्स

यह भेट दोनों राष्ट्रों के सार्थक संवाद में बदल जाती लेकिन हमारे प्रवक्ता ने चतुराई भरी कूटनीति करने की बजाय लट्टुमार राजनीति कर डाली। उसने नाम लिये बिना इमरान खान को फौज का मोहरा बता दिया और उन्हें 'तालिबान खान' सिद्ध कर दिया। इमरान और फौज के संबंधों के बारे में किसे पता नहीं है मगर ये ही संबंध ऐसा रूप भी धारण कर सकते हैं, जिसकी कल्पना आज तक किसी ने नहीं की है। यानी नेता आगे-आगे और फौज उसके पीछे-पीछे! इसका उल्टा होता ही रहता है लेकिन हमारी सरकार ने इमरान के आने पर जो नया मौका उसके हाथ लगा था, उसे गवां दिया है। इसका मूल कारण शायद यह है कि हमारी विदेश नीति का संचालन ठीक-ठाक नहीं है। भारत-पाक संवाद को पहले भी सिर्फ इसीलिए भंग कर दिया गया था कि पाकिस्तानी उच्चायुक्त से हुरियत के तेज़ प्रियों थे। उन्हीं

हात है। मिया नवाज ने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तुलना गंवारू औरत से कर दी थी किंतु इमरान ने मोदी के बारे में जो कहा है क्या वह उन पर भी लागू नहीं होता? बड़ी-बड़ी कुर्सियों में बैठने वाले कितने लोग सचमुच बड़े होते हैं? कुर्सियों से उतरने के बाद ज्यादातर राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों की कीमत उन कुर्सियों के बराबर भी नहीं रहती। इमरान के बोल ने इतने तीखे घाव कर दिए हैं कि उनकी दुर्गंध अब संयुक्त राष्ट्र महासभा को परेशान करेगी। कुरैशी कश्मीर की बीन बजाएंगे और सुषमा आतंकवाद का ढोल पीटेंगे। पता नहीं हमारे अगले चुनाव तक अब भारत-पाक संवाद पटरी पर आएगा या नहीं। चुनाव की इस बेला में यदि पाकिस्तान-विरोधी माहौल भारत में बना रहे तो यह मोदी के लिए मददगार ही होगा। इमरान के आने पर जो नई किरण फूटी थी, वह अभी उत्तर नहीं पार्ग तै।

देश की सरक्षा में महत्व का हवाईअड्डा

इसमें दो राय नहीं कि सिविकम का पाक्योंग ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा देश की बड़ी उपलब्धि है। इतने ऊंचे पहाड़ों को काटकर जिस ढंग से बनाया गया है, वह इसके योजनाकारों, इंजीनियरों, उनके साथ लगे सभी कर्मियों का असाधारण कारनामा है। यह हवाई अड्डा नहीं। सरकार की हवाई यात्रा को प्रोत्साहन देने के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा अभी भी हवाई अड्डों की भारी कमी है। दुनिया के अन्य अनेक देशों से तुलना करें तो भारत जैसे बड़े देश में केवल 100 हवाई अड्डे चालू अवस्था में हैं, जो इस मामले में द्वितीय पिछलेपन का प्रमाण है। उनमें ज्यादा प्रगति नहीं हुई। पाक्योंग हवाई अड्डे की आधारशिला भी 2009 में ही रखी गई थी। अगर काम की गति सही होती तो उसी सरकार के कार्यकाल में यह पूरा हो जाता। वास्तव में एक और हवाई यात्रा को प्रोत्साहन देने की नीति और दस्ती थोर पर्योन्तर के लिए एक



सभी भागों से जुड़ गया है। इसका सामरिक महत्व इस मायने में है कि यह चीन की सीमा से निकट है। इसका निर्माण भी उसी तरीके से हुआ है कि जरुरत पड़ने पर हम उसका सामरिक उपयोग कर सकते हैं। इन दिनों हवाई यातायात का महत्व कितना बढ़ में 35 हवाई अड्डे दिए हैं, तो इसे संतोषजनक प्रगति मानना होगा। इसे आगे बनाए रखने की आवश्यकता है। हालांकि इनमें से अनेक हवाई अड्डों की नींव यूपीए सरकार के दौरान डाली गई। किंतु उस सरकार में काम हुई है। पूर्वोत्तर में रेल का विस्तार पहले ही किया जा चुका है। उम्मीद करनी चाहिए कि हवाई सेवा के विस्तार का देशव्यापी काम तो चलता ही रहेगा, पूर्वोत्तर की विकास योजना भी इसी तरह आगे

संक्षिप्त समाचार

ओआईसी को कशीर मामले पर बोलने का कार्ड हक नहीं है : भारत

नई दिल्ली। भारत ने एक बार किसी पारिस्थितिक काम किए हैं। सिविकम को हवाई अड्डा मिलने से यह देश के शेष इलाकों से जुड़ गया और यह देश में सही मायने में



फटकारते हुए कहा है कि कशीर अंदरूनी मसला है और किसी 'बहुपक्षी ढांचे' के अंतर्गत इसे उठाना अस्तीकार्य है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें सत्र के इतर बुधवार को हुई इस्ट्रामिक सहयोग संघठन (ओआईसी) की बैठक में कशीर का मुद्दा उठाया था। जहां पाक विदेश मंत्री ने आरोप लगाया था कि 'भारत अधिकृत कशीर' के लोगों पर अत्याचार हो रहा है।

आधार को धन विधेयक के रूप में पारित करना धोखा : न्यायमूर्ति चंद्रचूड़

नई दिल्ली। आधार मुद्रे पर सर्वोच्च न्यायालय की पाच सदस्यीय पीठ के सदस्य न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने बुधवार को कहा कि आधार अधिनियम को धन विधेयक के रूप में नहीं लिया जा सकता और इसे धन विधेयक के रूप में पारित करना संविधान के साथ एक धोखा होगा। उन्होंने अपने एक अलग फैसले में कहा, 'आधार अधिनियम को धन विधेयक के रूप में नहीं लिया जा सकता। एक ऐसा विधेयक, जो कि धन विधेयक नहीं है, उसे धन विधेयक के रूप में पारित करना संविधान के साथ धोखा है।' न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के एक विधेयक को धन विधेयक के रूप में लिया जाए या नहीं, इस पर लोकसभा अध्यक्ष के फैसले को न्यायिक समीक्षा के लिए भाजा जा सकता है। उन्होंने कहा, आधार को धन विधेयक के रूप में नहीं लाया जाना चाहिए था। सदन का अध्यक्ष राज्यसभा की शक्तियों को नहीं छीन सकता, जो कि संविधान की एक रचना है। कोई शक्ति पूर्ण नहीं है। कुछ विदुओं पर अन्य न्यायमूर्तियों के साथ सहमति जताते हुए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने मुख्य विदु धन विधेयक और आधार की व्यवहारिकता की समनुव्यता के सिद्धांत के बारे में बिना नहीं किया।

इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण सफल

बालेश्वर (भाषा)। भारत ने रविवार तारीख को अंडिशन टट पर एक इंटरसेप्टर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसके साथ ही भारत ने दो परतों वाली बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली किसिसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली। रक्षा सूत्रों ने बताया, इंटरसेप्टर को अच्छुल कलाम द्वारा से रात में आठ बजकर पांच मिनट पर प्रक्षेपित किया गया। इसे पहले व्हीलर द्वारा के नाम से जाना जाता था। डीआईआईओ के वैज्ञानिक ने कहा, 'वाही रक्षा यान मिशन पूर्वी के वायुमंडल में 50 किमी से ऊपर की ऊंचाई पर लक्ष्य को निशान बनाने के लिए है।'

भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि देश में गठबंधन में असफल रही पार्टी

"भाजपा ने भी युनाव हारे, पर कभी ईपीएम को उसका दोष नहीं दिया"

अब भारत के 'बाहर' गठबंधन खोज रही है। मोदी मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की मध्यप्रदेश इकाई की ओर से यहां आयोजित कार्यकर्ता महाकूंभ को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने

पूर्वोत्तर को विकास गाथा का इंजन बनाए : पीएम मोदी

गंगटोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यहां कहा कि हम पूर्वोत्तर को भारत की विकास गाथा का इंजन बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पाकवींग्री ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा, यह दिन केवल सिविकम के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है। यह राज्य का पहली और देश का 100वां हवाई अड्डा है। इसके साथ ही हिमालयी ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे हैं और आप लोगों को यह जानकारी हैरानी होगी कि पिछले चार साल में देश को 35 हवाई अड्डे मिले हैं। इससे मालूम चलता है कि यह सरकार अधिकारी अंदरूनी ढांचों के विकास करने के लिए उत्तम प्रयत्न कर रही है।



काम किए हैं। सिविकम को हवाई अड्डा मिलने में मदद मिलेगी और पर्सिटन के बीत्र में पहले से विकसित यह राज्य और समृद्ध होगा। उन्होंने कहा, देश में अब 100 हवाई अड्डे हैं और आप लोगों को यह जानकारी हैरानी होगी कि पिछले चार साल में देश को 35 हवाई अड्डे मिले हैं। इससे मालूम चलता है कि यह सरकार अधिकारी अंदरूनी ढांचों के विकास करने के लिए उत्तम प्रयत्न कर रही है।

क्षेत्रीय संतुलन बनाने की दिशा में केन्द्र सरकार के लगन से काम कर रही है। मोदी ने हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद कहा, यह राज्य में अपनी कंपनी बनाई। बिना किसी से पूछे नरेंद्र मोदी ने 30 हजार करोड़ रुपए अनिल अंबानी के जेब में डाल दिया। आगे राहुल ने राफेल करार से 35 दिन पहले ही अनिल अंबानी ने 100 हजार करोड़ रुपए कर दिया। राफेल करार से 35 दिन पहले ही अनिल अंबानी ने 100 हजार करोड़ रुपए कर दिया।

क्षेत्रीय संतुलन बनाने की दिशा में केन्द्र सरकार के लगन से काम कर रही है। मोदी ने कहा कि यह राज्य में अपनी कंपनी बनाई। बिना किसी से पूछे नरेंद्र मोदी ने 30 हजार करोड़ रुपए अनिल अंबानी के जेब में डाल दिया।

राज्य का विकास करने के लिए उत्तम प्रयत्न कर रही है।

क्षेत्रीय संतुलन बनाने की दिशा में केन्द्र सरकार के लगन से काम कर रही है। मोदी ने कहा कि यह राज्य में अपनी कंपनी बनाई। बिना किसी से पूछे नरेंद्र मोदी ने 30 हजार करोड़ रुपए अनिल अंबानी के जेब में डाल दिया।

क्षेत्रीय संतुलन बनाने की दिशा में केन्द्र सरकार के लगन से काम कर रही है। मोदी ने कहा कि यह राज्य में अपनी कंपनी बनाई। बिना किसी से पूछे नरेंद्र मोदी ने 30 हजार करोड़ रुपए अनिल अंबानी के जेब में डाल दिया।

क्षेत्रीय संतुलन बनाने की दिशा में केन्द्र सरकार के लगन से काम कर रही है। मोदी ने कहा कि यह राज्य में अपनी कंपनी बनाई। बिना किसी से पूछे नरेंद्र मोदी ने 30 हजार करोड़ रुपए अनिल अंबानी के जेब में डाल दिया।

क्षेत्रीय संतुलन बनाने की दिशा में केन्द्र सरकार के लगन से काम कर रही है। मोदी ने कहा कि यह राज्य में अपनी कंपनी बनाई। बिना किसी से पूछे नरेंद्र मोदी ने 30 हजार करोड़ रुपए अनिल अंबानी के जेब में डाल दिया।

क्षेत्रीय संतुलन बनाने की दिशा में केन्द्र सरकार के लगन से काम कर रही है। मोदी ने कहा कि यह राज्य में अपनी कंपनी बनाई। बिना किसी से पूछे नरेंद्र मोदी ने 30 हजार करोड़ रुपए अनिल अंबानी के जेब में डाल दिया।

क्षेत्रीय संतुलन बनाने की दिशा में केन्द्र सरकार के लगन से काम कर रही है। मोदी ने कहा कि यह राज्य में अपनी कंपनी बनाई। बिना किसी से पूछे नरेंद्र मोदी ने 30 हजार करोड़ रुपए अनिल अंबानी के जेब में डाल दिया।

क्षेत्रीय संतुलन बनाने की दिशा में केन्द्र सरकार के लगन से काम कर रही है। मोदी ने कहा कि यह राज्य में अपनी कंपनी बनाई। बिना किसी से पूछे नरेंद्र मोदी ने 30 हजार करोड़ रुपए अनिल अंबानी के जेब में डाल दिया।

क्षेत्रीय संतुलन बनाने की दिशा में केन्द्र सरकार के लगन से काम कर रही है। मोदी ने कहा कि यह राज्य में अपनी कंपनी बनाई। बिना किसी से पूछे नरेंद्र मोदी ने 30 हजार करोड़ रुपए अनिल अंबानी के जेब में डाल दिया।

क्षेत्रीय संतुलन बनाने की दिशा में केन्द्र सरकार के लगन से काम कर रही है। मोदी ने कहा कि यह राज्य में अपनी कंपनी बनाई। बिना किसी से पूछे नरेंद्र मोदी ने 30 हजार करोड़ रुपए अनिल अंबानी के जेब में डाल दिया।

क्षेत्रीय संतुलन बनाने की दिशा में केन्द्र सरकार के लगन से काम कर रही है। मोदी ने कहा कि यह राज्य में अपनी कंपनी बनाई। बिना किसी से पूछे नरेंद्र मोदी ने 30 हजार करोड़ रुपए अनिल अंबानी के जेब में डाल दिया।

क्षेत्रीय संतुलन बनाने की दिशा में केन्द्र सरकार के लगन से काम कर रही है। मोदी ने कहा कि यह राज्य में अपनी कंपनी बनाई। बिना किसी से पूछे नरेंद्र मोदी ने 30 हजार करोड़ रुपए अनिल अंबानी के जेब में डाल दिया।

क्षेत्रीय संतुलन बनाने की दिशा में केन्द्र सरकार के लगन से काम कर रही है। मोदी ने कहा कि यह राज्य में अपनी कंपनी बनाई। बिना किसी से पूछे नरेंद्र मोदी ने 30 हजार करोड़ रुपए अनिल अंबानी के जेब में डाल दिया।

क्षेत्रीय संतुलन बनाने की दिशा में केन्द्र सरकार के लगन से काम कर रही है। मोदी ने कहा कि यह राज्य में अपनी कंपनी बनाई। बिना किसी से पूछे नरेंद्र मोदी ने 30 हजार करोड़ रुपए अनिल अंबानी के जेब में डाल दिया।

क्षेत्रीय संतुलन बनाने की दिशा में केन्द्र सरकार के लगन से काम कर रही है। मोदी ने कहा कि यह राज्य में अपनी कंपनी बनाई। बिना किसी से पूछे नरेंद्र मोदी ने 30 हजार करोड़ रुपए अनिल अंबानी के जेब में डाल दिया।

क्षेत्रीय संतुलन बनाने की दिशा में केन्द्र सरकार के लगन से काम कर रही है। मोदी ने कहा कि यह राज्य में अपनी कंपनी बनाई। बिना किसी से पूछे नरेंद्र मोदी ने 30 हजार करोड़ रुपए अनिल अंबानी के जेब में डाल